

Government should give certain powers to the Zila Parishads, as it has been done in some States. In some States, Zila Parishads are appointing the teachers, constructing the buildings and so on. They will be nearer to the people. I agree that decentralisation is going to help in the development of primary schools. In principle, I agree with the hon. Member on this point. We have no objection if the State Government decides it.

**मुजफ्फरनगर और मेरठ में रेलवे बुलों का निर्माण**

\*423. श्रीमती मातृती शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बातों को कृपा करेंगे कि:

(क) गत दोष वर्षों के दौरान देश में कुल कितने रेलवे बुलों का निर्माण किया गया और उनका खर्च-चार बीघा क्या है;

(ख) वर्ष 1996 में कितने रेलवे बुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ में रेलवे बुलों के निर्माण हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी नोट क्या है; और

(ङ) उक्त रेल बुलों का निर्माण-कार्य कब तक सम्पन्न कर दिया जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री राम बिलास बासवान):** (क) से (ङ) इस विषयक कुछ बातें यह कहा किया गया है।

#### विवरण

(क) राज्यवार नोट इस प्रकार है—

अन्य प्रदेश	—	6
बिहार	—	3
दिल्ली	—	6
गुजरात	—	2
हरियाणा	—	5
जम्मू-काश्मीर	—	1
कर्नाटक	—	1
केरल	—	2
कन्नड़ प्रदेश	—	5
महाराष्ट्र	—	4
उड़ीसा	—	3
पंजाब	—	3

इसरातान	—	1
उत्तराखण्ड	—	2
उत्तर प्रदेश	—	5
पश्चिम बंगाल	—	1

**कुल:** 52

(ख) अनुमानित।

(ग) से (ङ) क्या प्रश्नों के सबसे उत्तर/ निम्ने सवाल बुलों के निर्माण के बारे में देश सरकार में विचारों के अन्तर्गत पर विचार किया है और उनके लिए क्या सरकार की अपने विचारों की समझा समझ करने की समझति देती हुए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करने छोटी है। मुजफ्फरनगर और मेरठ के लिए कुछ कुछ यह कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। महाराष्ट्र, मेरठ शिले में से उम्मीद सवाल बुलों के निर्माण का कार्य स्वीकृत है, निम्ने से एक किलोमीटर 59/6-7 पर समझा समझा 21-ए के बगले बगल में और दूसरा किलोमीटर 91/8-9 पर समझा समझा 40-बी के बगले समझा-समझा में है।

श्रीमती मातृती शर्मा: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी समझा समझा से पुल बनाने स्वीकृत कर दिए हैं। किन्तु माननीय मंत्री जी मैं अपने उत्तर में 'ग' भूमि पर उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा है चाहती हूँ कि ये पुल नब तक बनाना प्रारंभ हो जायेगा और कब तक उनको बनाकर समाप्त कर दिया जाएगा?

श्री राम बिलास बासवान: सभापति जी, किसी भी पुल की जब हम स्वीकृति देते हैं तो उसकी जवाबदेही पहले राज्य सरकार पर जाती है। राज्य सरकार का काम होता है कि जमीन का वह इन्फ्रस्ट्रक्चर करे और उस बाद हम फंड देते हैं, फंड देने वह हम काम करते हैं। परतपुर में और समझा समझा टांडा में—समझा समझा टांडा ज. प्रोजेक्ट है वह 1987-88 में सेक्शन किया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मुजफ्फरनगर और मेरठ के इलाके कितने महंगे पड़ते हैं। इसलिए जिनकी जमीन है वे जमीन देते नहीं हैं और कभी-कभी रिप्रजेंटेटिव्स आ जाते हैं इसको इधर से उधर कीविए। इसको इन्कलूड किया गया था 1987-88 में। लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया। फिर अन्य लोगों ने जब प्रेशर डाला और कहा तो उसको फिर इन्कलूड किया गया है। राज्य सरकार से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जमीन का अधिग्रहण किया जा

खा है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है, यह इस संबंध में नहीं है। लेकिन इनकी चुनौती मिली है कि जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। उसी तरह से यह सर्वेक्षणी दंडित कर है। भूतलपट्टा का भी मामला है। इसको 1994-95 में टेकअप नहीं किया गया था। अब सैक्शन किया गया है। सैक्शन तो कर दिया है लेकिन अभी तक सेट गवर्नमेंट ने इस संबंध में जो कार्रवाई शुरू करनी चाहिए वो जमीन अधिग्रहण बगैरह की, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

एक चीज उसके लिए आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वह है मुजफ्फरनगर में—फुट ओवर थ्रिज विलकॉम मैन का फ्लैट नहीं बना था। लेकिन बुकिंग आप उस मामले में इन्वेस्ट निश्चयी नहीं है, तो आपको जानकारी के लिए मैं यह बताता हूँ कि वर्ष 1997-98 के प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर दिया गया है।

**श्रीमती भारती शर्मा:** मानवर, माननीय मंत्री जी ने पुल की भी बात कर दी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं केवल इसकी जानकारी चाहती हूँ कि वो वर्ष पहले मेरी नगर से भेरा तक के लिए उनका टर्नइन का प्रस्ताव सरकार ने क्या किया था। यह उनका टर्नइन आज तक प्रारम्भ नहीं हुई। मैं आपसे यह जानकारी चाहती हूँ कि केवल यह कागजों पर ही पुल बनेंगे या फिर हम जनता को जाकर क्या बताएं कि यह पुल बनने का यह प्रारम्भ हो जाएंगे। यह सरकार और आपके बीच की जो कार्रवाई है उसको जल्द नहीं जानती, आप जानते हैं। मैं तो केवल आपसे यह जानकारी चाहती हूँ कि क्या तक आप इस पुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा देंगे? अन्यथा तो यहां कुछ दुकानें बंदी हुई हैं। यह दुकानदार लोग सरकार से से लेते हैं कमी आप जमीन के अधिग्रहण की क्या कर देंगे। तो फिर माफ़सत खराई में यह जाएगा। इसलिए मैं मंत्री जी से जानकारी चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है। आप मुझे आश्वासन देंगे कि यह पुल नव तक बनना प्रारम्भ हो जाएगा?

**श्री राज विमल चारुवाण:** माननीय सदस्य सिर पुल के संबंध में पूछ रही हैं। वह अब उनका टर्नइन के संबंध में पूछ रही हैं?

**श्रीमती भारती शर्मा:** पुल नम्बर-80, पल्लवी टाक। फुट ओवर थ्रिज मुजफ्फरनगर सेले रोड। रोड के विषय में।

**श्री राज विमल चारुवाण:** मैं लोग की स्थिति जानने चाहती कि अपनी सरकार से क्या सरकार की

लिखेंगे। राज्य सरकार में नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार को लिखूंगा। हमारा जो रेलवे का पैसा है, होकर है हम तैयार रखे हुए हैं। जब राज्य सरकार काम शुरू कर देगी हम अपना पैसा उसमें डाल देंगे।

**श्रीमती भारती शर्मा:** माननीय मंत्री जी, मैं केवल आपसे इन्वेस्ट निवेदन करना चाहती हूँ कि सखी से आप अपनी सरकार को लिखिए कि वह यहां जमीन का अधिग्रहण जल्दी करे। इसका आश्वासन आप हमें दें कि आप क्या तक कार्रवाई करेंगे?

**श्री राज विमल चारुवाण:** हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो जो सरकार होगी इसको हम लिख देंगे।

**श्रीमती भारती शर्मा:** मेरा लेवेंट क्वेश्चन है—तृतीयमंटी।

MR. CHAIRMAN: You put your second question.

**श्रीमती भारती शर्मा:** माननीय मंत्री जी ने 5 फुट के बनाने की बात कही है उत्तर प्रदेश में। यह 5 फुट जैन-मौन से है?

**श्री राज विमल चारुवाण:** सभापति महोदय, मुजफ्फरनगर और मेरा में जो अभी तक पुल निर्माण हो रहा है वह गतिविधियां, तहसनपुर, मेरा में है। दूसरा मुजफ्फरनगर में, तीसरा मुजफ्फरनगर में है। जो है उनका मैं विवरण दे दिया है। जो आवश्यकता है उनका मैं पता भी लगाया कि कहां-कहां बनाने की आवश्यकता है। उसमें मेरा कैट का मामला है, उसमें दोपल है, बतौली में है, मुजफ्फरनगर में है, रामली में है। वह जो पांच जगह है वहां पुल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन वैसे कि मैं बता कि जो आवश्यकता है उसकी रिकमंडेशन सेट गवर्नमेंट की तरफ से जाती है। जो सेट गवर्नमेंट की तरफ से जाता है वो केबने उसको अपर विचार करता है। वो सेट गवर्नमेंट की तरफ से जाती है वहां तक इसके संबंध में डिपेंड नहीं आया है।

**श्री महेन्द्र नाथ ओझा:** सभापति महोदय, रेलवे के सेले की पुल है जो इसी वर्ष प्रारम्भ में है कि उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है और ट्रेड का कारोबार फेलोवर्स देन से उनका के सब नहीं है। मेरी विनम्र प्रार्थना है जो इस प्रस्ताव में है और मैं इसी के साथ अप्रारम्भ देन चाहूँ कि कानपुर मंडल के अंदर पूर्वी रेलवे की मुजफ्फरनगर में एक सेल की पुल है।

जो बन नहीं रहा है और वहां एक-दो ऐसे इंसोडेंट भी हुए कि रेल से कटकर लोग मरे। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम से उतरकर इस बार या उस बार जाने के लिए जो अभी जर्ज हालत में ब्रिज है उसकी मरम्मत के लिए या उसको बनाने के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं?

**श्री राम बिलास पासवान:** महोदय, जहां तक रेलवे के पुल का सवाल है उसमें तो हमेशा हम इन्वॉयरी करवाते रहते हैं। कहीं कोई भी पुल अभी तक ऐसा नहीं आया है जो रेलवे का हो और टूटा हो या इस तरह का हो। माननीय सदस्य ने जिस पुल को, डुमरांव के पुल का कहा है, उस पुल की जांच करावाएंगे उसमें रेलवे का कितना मायला है या कितना पुल का पुराना होने का मामला है या स्टेट गवर्नमेंट का है। हम उसकी जांच करावाएंगे।

**एक माननीय सदस्य:** बिल्कुल रेलवे का है।

**श्री ईश दत्त बादव:** सभापति जी, श्रीमती मालती शर्मा जी का जो प्रश्न है, इसी आशय का प्रश्न पिछले सत्र में भी इनका था। उस समय भी मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिला था। आज भी आप की महती कृपा है। उस समय जो मैंने प्रश्न पूछा था, वही फिर माननीय रेल मंत्री जी से पूछने जा रहा हूं। उस समय उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उनके प्रयास से इटावा में रेलवे अंडर ब्रिज बनाने के लिए रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था। श्री जनेश्वर मिश्र जी, तत्कालीन रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गयी। तो दुर्भाग्य से उस समय की सरकार ने इस अंडर ब्रिज का बनना रोक दिया। फिर जब मैंने श्री जाफर शरीफ साहब को, रेल मंत्री जी को इसके संबंध में पत्र लिखा और श्रीमती मालती शर्मा जी के प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछ तो तत्कालीन रेल मंत्री जाफर शरीफ साहब ने आश्वासन दिया कि जून सन् 1996 तक इटावा का रेलवे अंडर ब्रिज पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन मानव, काम शुरू नहीं हो सका। श्री राम गोपाल बादव जी, जो हमारे माननीय सदस्य हैं इस सदन के इन्होंने एक पत्र...

**MR. CHAIRMAN:** Please put the question. Don't tell the whole story.

**श्री ईश दत्त बादव:** नहीं सर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

माननीय राम बिलास पासवान जी को लिखा और इन्होंने आश्वासन दिया—मैं इनकी प्रशंसा करूंगा—कि

इस पुल पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इनके आदेश से कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया है लेकिन गति बहुत धीमी है और माननीय रेल मंत्री, पासवान जी ने आश्वासन दिया है कि अब जून 1997 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि जिस धीमी गति से यह काम हो रहा है, वह काम पूरा नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि आपने जो समय निश्चित किया है, समय दिया है उसके अंदर क्या पूरा करने की कोशिश करेंगे?

**श्री राम बिलास पासवान:** हम पूरा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम पूरा करावाएंगे यदि मुझे रहने का मौका मिला तो .... (ब्यवधान) सरकार सरकार है ... (ब्यवधान)

जहां तक पुल का सवाल है, पुल सैक्स्ट है, काम प्रोग्रेस पर है। मुलायम सिंह बादव जी ने भी हमसे कहा था, राम गोपाल जी ने भी हमसे कहा था। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है इसी पुल के संबंध में ही नहीं बल्कि मेरी मान्यता है कि जो काम टेक अप किया है वह जल्द से जल्द हो और उसको पूरा कर लिया जाए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि उस काम में ढिलाई होगी तो वह ढिलाई नहीं करने दी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो कभी उस हस्ते से चलेंगे तो हम इटावा भी पहुंच जाएंगे।

**श्री सूर्यभान पाटिल बाह्रदने:** माननीय सभापति जी, रेलवे क्रॉसिंग पर चार पुल महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। उनके नाम क्या हैं और राज्य की ओर से जो राशि आनी चाहिए केन्द्र की ओर, वह आई है या नहीं और वह राशि कितनी है?

**श्री राम बिलास पासवान:** उसका पूरा विवरण आपको भेज दूंगा।

**DR. ALLADI P. RAJKUMAR:** I would like to know from the hon. Minister the number of bridges pending in Andhra Pradesh. How many have been sanctioned in 1996-97? What is the Budget allocation for these projects? For the last 10 years we have been requesting for sanction of two flyovers—one, Sitafal Mandi and one, Jamia Osmania bridge—but nothing has happened so far. Ten years back I had made a representation and it is being negotiated since then. Would the Minister reply to these questions?

श्री राम बिलास पासवान: सर, आन्ध्र प्रदेश में जो निर्माणधीन पुल हैं वे 1996-97 के मुताबिक 17 हैं और बाकी जो चीज़ आपने डिटेल् में मांगी है उसकी भी हम लिख कर भेज देंगे।

#### Potential Landing Sites for Fish in Andhra Pradesh

\*424. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to update the techno-feasibility studies done on potential landing sites for fish on the coast of Andhra Pradesh;

(b) if so, when was the study done;

(c) the names of potential fish landing centres thus studied in Andhra Pradesh; and

(d) the economic potential of each such site?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to

(d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

#### Statement

(a) to (d) The Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore, after collecting techno economic data during May, 1996 in collaboration with the State Government have now taken up the job of preparing the techno-economic feasibility report for the development of fishing harbour at Krishnapatnam in Nellore district of Andhra Pradesh.

The Government of Andhra Pradesh have also conducted techno-feasibility studies during 1994 and shortlisted four sites for setting up fish landing centres, namely (1) Pedamainavanilanka in West Godavari district, (2) Chinnagollapalem in Krishna district, (3) Gondisamudram (Nakshatrapuram) in Guntur district (4) Gundayapalem in Prakasam district.

The estimated fish landings, their value and number of fishing villages covered by each site are as follows:

Possible sites identified for Fishing Harbours/Fish Landing Centres	Estimated catch (m. tonnes)	Estimated value (Rs.)	Estimated beneficiaries (nos)	
			Villages	Fishermen
1. Kirishnapatnam	18,200	18,00,00,000	6	3224
2. Pedamainavanilanka	958	1,72,44,000	1	690
3. Chinnagollapalem	15,300	27,54,00,000	5	6000
4. Gondisamudram (Nakshatrapuram)	503	90,54,00,000	8	1403
5. Gundayapalem	900	1,62,00,000	1	500

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, Andhra Pradesh has a long coastal line and there is a great potential for developing the fishing industry there. I would like to know what steps the Government is taking to develop landing centres in Andhra Pradesh in the 9th Five Year Plan. It is

felt that there is potential for developing fishing centres near Narsapuram in West Godavari district and in Nizampatnam near Guntur. But they have been ignored by the Fishery Development Authority of the Ministry. How does the Government propose to assist the Andhra Pradesh Government in developing such landing centres?